संपादकीय

कारोबार नहीं जनकल्याण हो प्राथमिकता

जीवन में असुरक्षा, स्वास्थ्य व अपनों के भविष्य की तमाम चिंताओं से मुक्ति के लिये कोई व्यक्ति बीमा का सुरक्षा कवच लेने को बाध्य होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह विश्वास होता है कि ऊंच-नीच के वक्त में यह बीमा मददगार साबित होगा। लेकिन विडंबना यह है कि जिस बीमा क्षेत्र का आधार विश्वास होना चाहिए, उसको लेकर पॉलिसी धारकों में लगातार अविश्वास बना रहता है। बीमा कराने वाले एजेंटों और कंपनियों की ढकी-छिपी शर्तें उपभोक्त ाओं के मन में अकसर संशय के बीज बोती हैं। जब बीमाधारकों को पॉलिसी का लाभ लेने का वक्त आता है तो उन्हें तमाम जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। हाल में आयोजित किए गए सर्वेक्षण ने इस वास्तविकता पर मोहर ही लगायी है। सर्वेक्षण बीमा क्षेत्र की तमाम विसंगतियों को उजागर ही नहीं करता बल्कि एक कठोर वास्तविकता की ओर भी इशारा करता है। सर्वेक्षण का निष्कर्ष है कि बीमा क्षेत्र में व्याप्त तमाम विसंगतियों को दूर करने के लिये लगातार निगरानी करने वाले एक सख्त नियामक तंत्र की आवश्यकता है। सर्वेक्षण के निष्कर्ष कई गंभीर खामियों की ओर इशारा करते हैं। इसके निष्कर्षों के अनुसार भारत के लगभग 65 फीसदी बीमा पॉलिसी धारकों को नहीं पता होता है कि उन्हें पॉलिसी लेने से कौन-कौन से लाभ होते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि पॉलिसी से बाहर निकलने की प्रक्रिया कैसी है। यह भी नहीं मालूम कि दावा प्रक्रिया की आवश्यक कार्यवाही को उन्हें कैसे अंजाम देना है। इतना ही नहीं लगभग 60 फीसदी आश्रितों को यह भी नहीं पता कि वे किसी पॉलिसी के अंतर्गत कवर हैं। वे इस बात से अनजान हैं कि उन्हें किस चीज व किस स्थिति में बीमा लाभ मिलेगा। कमोबेश यह स्थिति तब है जब देश में बीमा उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। निस्संदेह, यह समझ की कमी केवल उस शब्दावली से ही नहीं उपजी है जिसे समझना मुश्किल है, बल्कि बीमा करते समय उपभोक्ता को उसकी प्रक्रिया और लाभों का सिर्फ एक पक्ष ही बताया जाता है। कई वास्तविकताएं शब्दजाल में छिपा ली जाती हैं। निश्चित रूप से बीमा का मूल उद्देश्य तब विफल हो जाता है, जब बीमाकर्ता उपभोक्ताओं को सही ज्ञान और लाभ लेने की वास्तविक प्रक्रिया की जानकारी देने के मूल कर्तव्य में विफल हो जाता है। दरअसल, विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री भी एक प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई है। जो कि पहले ही चरण में वित्तीय सुरक्षा के अंतिम लक्ष्य को कमजोर कर देती है। आम धारण बन गई है कि बीमा उद्योग इससे जुड़ी कंपनियों के आर्थिक हितों और जन के हितों के टकराव के रूप में स्थापित है। इसमें जनहित की प्राथमिकता नहीं होती बल्कि कंपनी का मुनाफा कमाने को तरजीह दी जाती है। अपना टारगेट पूरा करने के लिये उपभोक्ताओं को जबरन पॉलिसी चिपकाने वाले एजेंटों से लेकर ऐसे फील्ड अफसरों की लंबी सूची है, जिनकी प्राथमिकता बीमा कंपनी को लाभ पहुंचाने की ही होती है।

विनोद शर्मा, संपादक

संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते राहुल गांधी

डॉ. आशीष वशिष्ठ

हालांकि राहुल गांधी के पूर्व रिकार्ड के हिसाब से ऐसा लग नहीं रहा है कि वो चुनाव आयोग के सामने जाएंगे। इसके लिए उन्होंने अभिषेक सिंघवी, विवेक तन्खा जैसे बड़े वकीलों और पार्टी के अन्य नेताओं को रखा हुआ है। राहुल गांधी का काम सिर्फ आरोप लगाना है। अगर एजेंसी आरोपों को जवाब देना चाहती है तो वह सुनना उनका काम नहीं है। कमोबेश ऐसा ही आचरण उनका संसद में भी है। असल में] राहुल गांधी आरोप लगाकर, सामने वाले का पक्ष या जवाब सुनने की बजाय कोई नया आरोप लगाने की तैयारी में जुट जाते हैं। तथ्य और तर्क से उनका कोई लेना देना नहीं रहता। तथ्य यह भी है कि नवंबर 2024 में विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस की ओर से इसी तरह के मुद्दे उठाए गए थे। आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस पार्टी को एक विस्तृत जवाब दिया था, जिसकी प्रति चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी इस अध्याय का पटाक्षेप नहीं चाहते हैं। उनकी पार्टी इस मामले को जिंदा रखना चाहती है ताकि आगे के चुनाव नतीजों को सुविधा को हिसाब से संदिग्ध बनाया जा सके।

नवंबर 2024 में महाराष्ट्र चुनाव में करारी पराजय के बाद कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी दलों ने चीखना शुरू कर दिया था- ईवीएम में भूत है, जो भाजपा को ही वोट भेजता है।' अप्रैल 2025 को विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान बोस्टन में एक मीटिंग को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र चुनाव का हवाला देते हुए, चुनाव पर बड़े सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में चुनाव आयोग कंप्रोमाइज्ड है। ताजा संदर्भ राहुल गांधी ने 'मैच-फिक्सिंग महाराष्ट्र' शीर्षक से 7 जून को एक लेख लिखा। ये कई अखबारों में छपा। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं और भाजपा ने सुनियोजित तरीके से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया। यह कोई पहला ऐसा मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठया हो या फिर उन्हें कटघरे में खड़ा करने का काम किया हो। वो आदतन अक्सर ऐसा करते रहते हैं । भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित करता है जिसे संसद, राष्ट्रपति, विधानसभा और सभी निर्वाचित निकायों के चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने का दायित्व दिया गया है। यह संस्था न तो कार्यपालिका के अधीन है और न ही किसी राजनीतिक दबाव में काम करती है। भारतीय निर्वाचन आयोग केवल एक प्रशासनिक निकाय नहीं बल्कि विवाद-निराकरण और मतदाता-विश्वास निर्माण की भी जिम्मेदारी निभाता है। आयोग मतदान प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाने के लिए कई स्तर पर काम करता है। राहुल गांधी सस्ती लोकप्रियता पाने के कुछ भी बयान देते हैं, पर तर्क और तथ्य की कमी होती है। इससे समाज में भ्रम फैलता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर पड़ती है। विदेशी धरती पर जाकर वो देश का अपमान, मोदी सरकार की आलोचना और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का कोई अवसर चूकते नहीं हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने अमेरिका के नेशनल प्रेस क्लब में कहा कि भारत में लोकतंत्र पिछले 10 सालों से टूटा (ब्रोकेन) हुआ था, अब यह लड़ रहा है। उनका यह कहना लोकतंत्र की मूल भावना पर ही सवाल उठाता है। खासकर तब जब भारत में लगातार चुनाव होते रहे हैं और सरकारें बदलती रहीं हैं। बीते 10-11 वर्षों में देश में कई ऐसी सरकारें बनी हैं, जिसे बीजेपी को हराने के बाद कांग्रेस को मौका मिला है। मतलब, अगर नतीजे राहुल और उनकी पार्टी के लिए अच्छे रहें तो लोकतंत्र ठीक है और नहीं तो वह ब्रोकेन हो जाता है। सितंबर 2023 में राहुल गांधी ने ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन में कहा कि भारत में फुल स्केल एसॉल्ट हो रहा है। उन्होंने भारतीय संस्थाओं की निष्पक्षता पर संदेह जताया। मई 2022 में लंदन में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में राहुल ने कहा कि भारत की संस्थाएं परजीवी बन गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि डीप स्टेट (सीबीआई, ईडी) भारत को चबा रहा है। यहां डीप स्टेट का मतलब सरकार के अंदर छिपे हुए ऐसे ताकतवर लोग हैं जो अपने फायदे के लिए काम करते हैं। राहुल गांधी ने भारत की तुलना पाकिस्तान जैसे अस्थिर लोकतंत्र से भी कर दी। 2017 में ही अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा कि भारत अब वह नहीं रहा जहां हर कोई कुछ भी कह सकता है। उन्होंने विदेश की धरती पर भारत में फ्री स्पीच की स्थिति पर संदेह पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भारत में सहनशीलता खत्म हो गई है। जबकि, हकीकत ये है कि राहुल गांधी संसद से लेकर बाहर तक जब जो जी में आता है, बयान देते रहे हैं और सरकार को छोड़ दें, शायद ही कोई संवैधानिक संस्था बची हो, जिस पर उन्होंने निशाना न साधा हो। राहुल गांधी यह क्यों भूल जाते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग ने ही वे चुनाव संपन्न करवाए हैं, जिनके दम पर वह आज विपक्ष के नेता पद पर बैठे हुए हैं। उनके परिवार के तीन-तीन सदस्य इन्हीं चुनावी प्रक्रियाओं का सहारा लेकर संसद में मौजूद हैं। यहीं की संवैधानिक संस्थाओं ने उन्हें इतनी राहत दी हुई है कि नेशनल हेराल्ड केस में गंभीर आरोपों के बावजूद वो और उनका मां सोनिया गांधी को जमानत मिली हुई है। बीते कुछ वर्षों में राजनीतिक तौर पर भले ही भारत की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठने का चलन बन गया हो लेकिन भारत के चुनाव आयोग की प्रशंसा केवल देश के भीतर ही नहीं संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षकों और कई विदेशी सरकारों द्वारा भी की गई है। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के 2020 के एक अध्ययन में भारत के चुनाव आयोग को 'वन ऑफ़ दी मोस्ट रोबस्ट इलेक्टोरल इंस्टीटूशन्स ग्लोबली' (विश्व स्तर पर सबसे मजबूत चुनावी संस्थाओं में से एक) कहा गया। यही नहीं, 2014, 2019 और 2024 के आम चुनावों में भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया कि तकनीक, प्रशिक्षण और जनता की भागीदारी के माध्यम से एक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संभव है। बीती मई को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने से चुनाव आयोग से मुलाकात कर चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया था। यह बातचीत निर्वाचन आयोग की उस नई पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक दलों की चिंताओं और सुझावों को सीधे तौर पर सुनकर चुनावी प्रक्रिया को अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाना है। चुनाव आयोग अब तक देशभर में कुल 4,719 सर्वदलीय बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इन बैठकों में अब तक 28,000 से अधिक राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से लिखित में तथ्यों की मांग की और चर्चा के लिए भी आमंत्रित किया है।

हिमालय के आंचल में बर्फानी बाबा के दिव्य दर्शन

डॉ. जवाहर धीर

आदिदेव भगवान शिव को नीलकंठ, केदारनाथ, त्रिनेत्रधारी, अर्धनारीश्वर, बर्फ़ानी बाबा आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। अगर यह कहा जाए कि शिव भारतीय जनमानस के सर्वाधिक पूजनीय देवता हैं, तो ग़लत नहीं होगा। भारत के राज्य जम्मू-कश्मीर में पीर पंजाल के पर्वतों में स्थित श्री अमरनाथ श्राइन में उनके अपने आप बनने वाले बर्फ के शिवलिंग के रूप में स्थापित होने की घटना को अपनी आंखों से देखने के लिए सदियों से प्रतिवर्ष लाखों लोग अत्यंत श्रद्धा से वहां जाते हैं। बर्फ़ीले पर्वतों में स्थित श्री अमरनाथ गुफा, प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह गुफा भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को अमरकथा सुनाने का पवित्र स्थल मानी जाती है। प्राकृतिक रूप से निर्मित हिमलिंग के दर्शन हेतु शिवभक्त वर्षभर प्रतीक्षा करते हैं। गुफा हर समय बर्फ़ से घिरी रहती है और इसका आकार लगभग 60 फीट चौड़ा, 30 फीट लंबा व 15 फीट ऊंचा है। श्रीनगर से 125 किलोमीटर दूर इस गुफा तक दो मुख्य मार्ग हैं–एक अनन्तनाग से पहलगांव होते हुए और दूसरा गांदरबल जिले का बालटाल मार्ग, जिसे सेना ने अब सुरक्षित और सुविधाजनक बना दिया है। बालटाल से यह 13.2 किलोमीटर का मार्ग चौड़ा कर दिए जाने के कारण अब श्रद्धालु चार से पांच घंटे में गुफा तक पहुंच सकते हैं। पर्यटन स्थल पहलगाम अमरनाथ यात्रा के परम्परागत मार्ग का प्रथम पड़ाव है। पहलगाम से सोलह किलोमीटर दूर चंदनवाड़ी नामक स्थान है, जहां यात्री सुबह-सुबह पहुंच कर पैदल यात्रा प्रारम्भ करते हैं और शेषनाग, पंचतरणी में रात्रि विश्राम के बाद अगली सुबह अमरनाथ गुफ़ा के दर्शन करने जाते हैं। दर्शन करने के बाद कुछ यात्री बालटाल के मार्ग से लौटते हैं तो कुछ पहलगाम वाले रास्ते से लौट पड़ते हैं। दोनों ओर के रास्तों से छड़ी के सहारे आना जाना पड़ता है। श्री अमरनाथ गुफ़ा का सारा मार्ग हिमाच्छादित पर्वत शृंखलाओं, विशालकाय पर्वतों एवं संग-संग बहते झरनों और कल-कल करती नदी के साथ मानव को प्रकृति की इस अलौकिक छटा के दर्शन होते हैं। गुफ़ा से साढ़े तीन किलोमीटर पहले यह मार्ग बर्फ़ के बने उस पुल को पार करने से जुड़ा है, जिसके नीचे तक अमर गंगा निर्बाध रूप से बहती रहती है और ऊपर से मानव बिना किसी भय के चलता जाता है। इस पुल के ऊपर खड़े होकर चारों ओर बर्फ़ से ढकीं पर्वत मालाओं को निहारना शिवभक्तों की मानसिक और शारीरिक थकान को दूर करती चोटियां प्रकृति का मनोरम उपहार है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार भगवान श्री शिव सर्व प्रथम श्रावणी पूर्णिमा को ही इस शिवलिंग में स्थित हो गये थे और प्रत्येक श्रावणी पूर्णिमा को यहां प्रकट होने का वर दिया था। इसी कारण से इस दिन हिमलिंग के दर्शनों का विशेष महत्व माना गया है। उल्लेखनीय है कि आदिकाल में पहलगाम को नंदीग्राम नाम से जाना जाता था, फिर बैलगांव और बाद में समय के साथ पहलगांव या पहलगाम नाम से पुकारा जाने लगा। यहां से चंदनवाड़ी होते हुए लगभग चौदह किलोमीटर दूर शेषनाग झील के किनारे बसे तम्बुओं के अस्थाई नगर में रात्रि विश्राम की व्यवस्था होती है। शेषनाग झील, जिसके पार्श्व में ब्रह्मा, विष्णु और महेश नामक पर्वत शृंखलाएं हैं, स्वर्ग की कल्पना जैसी शांत, गहरे हरे नीले रंग की मनोरम झील है, में मान्यता है कि श्री शिव ने अपने गले में धारण किए शेषनाग को छोड़ा था। यहां के 12300 फीट की ऊंचाई पर बने बर्फ़ के पुल को पार करके आगे महागुणस पर्वत है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तट से 14000 फीट है। इसके आगे का पंचतरणी तक का मार्ग उतराई का मार्ग है। पंचतरणी में बहती जलधारा की पांच धाराएं प्रकृति के मनमोहक दृश्य का दर्शन करके प्राणी आनन्द विभोर हो जाता है। यहां से सात किलोमीटर दूर पावन गुफ़ा है, जहां पहुंचने से पहले लगभग साढ़े तीन किलोमीटर दूर संगम नामक स्थान है जहां बालटाल से आता मार्ग संगम में मिलकर एक हो जाता है। बालटाल वाला मार्ग श्रीनगर से 92 किलोमीटर की दूरी पर सोनमर्ग की खूबसूरत वादियों में से जाता हुआ समय की दृष्टि से काफी निकट है। इस मार्ग से जाने वाले यात्री एक ही दिन में दर्शन करके लौट आते हैं। बालटाल से बहुत से यात्री हेलीकॉप्टर से पंचतरणी के पास बने हैलीपेड तक जाया करते रहे हैं। गुफ़ा के भीतर दाईं ओर पर्वत के ऊपर से बूंद-बूंद करके गिरने वाले जल से हिमलिंग का निर्माण होता है।

बाढ़जनित हादसों में कब तक होती रहेगी जन-धन की हानि

योगेंद्र योगी

देश में सरकारी मशीनरी की तंद्रा तब भंग होती है, जब कोई बड़ा हादसा हो जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकारी तंत्र जागने के लिए बड़े हादसे की इंतजार में रहता है। पहले हुए हादसों से सबक सीखने की जरूरत महसूस नहीं की जाती। इसकी प्रमुख वजह है जिम्मेदारी का अभाव। यदि यह जिम्मेदारी तय कर दी जाए कि किसी तरह के हादसे के जिम्मेदारी संबंधित विभागों के अफसरों की होगी और हादसा होने की सूरत में उन्हें सख्त सजा मिलेगी, तभी हादसों पर लगाम लगाई जा सकती है। अभी मानसून की शुरुआत है। हर साल मानूसन के दौरान देश में बाढ़ जनित हादसों में सैकड़ों लोगों की मौत होती है। भारी बारिश से देश को अरबों रुपयों की सम्पत्ति का नुकसान होता है। जन-धन की इस हानि की किसी जिम्मेदारी तय नहीं है। आखिर कौन हर साल होने वाले ऐसे हादसों के लिए जिम्मेदार है। हादसा होने के बाद सिर्फ लकीर पीटी जाती है। ऐसे उपाय नहीं किए जाते कि हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो, या फिर इनकी संख्या में कमी लाई जा सके।भारत में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान में तेजी से वृद्धि हुई है। 2013-2022 के दशक में हर साल औसतन 8 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 66,000 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ। यह 2003-2012 के दशक की तुलना में 125 फीसदी अधिक है, जब यह आंकड़ा 3.8 अरब डॉलर था। वर्ष 2024 के नुकसान की गणना अभी बाकी है, जो इतिहास में भारत का सबसे गर्म साल रहा है। यह वृद्धि बताती है कि या तो प्राकृतिक आपदाएं अधिक बार आ रही हैं, अधिक गंभीर हो गई हैं, या दोनों ही बातें हो रही हैं। 1970 से 2021 तक का डेटा दिखाता है कि समय के साथ प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान में लगातार बढ़ोतरी हुई है। कुछ वर्षों में नुकसान की मात्रा में बड़ी छलांग देखी गई, जो विनाशकारी घटनाओं, जैसे कि बड़े चक्रवातों, बाढ़, या सूखे के कारण हुई। वर्ष 2023 में, भारत को प्राकृतिक आपदाओं से 12 अरब अमेरिकी

डॉलर (एक लाख करोड़ रुपये से अधिक) का नुकसान हुआ। यह 2013-2022 के औसत 8 अरब डॉलर से काफी ज्यादा था। स्विस रे की रिपोर्ट के अनुसार, ये बड़े नुकसान उन क्षेत्रों में हुए जहां संपत्तियों और आर्थिक गतिविधियों की संख्या ज्यादा है। स्विस रे एक प्रमुख पुनर्बीमा कंपनी है, जो विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट और अध्ययन प्रकाशित करती है। जून 2023 में, चक्रवात बिपरजॉय ने गुजरात के कच्छ जिले में भारी नुकसान पहुंचाया। इसके कारण सौराष्ट्र और कच्छ के सभी बंदरगाह, जैसे कांडला और मुंदरा बंदरगाह, बंद हो गए। तेज हवाओं, भारी बारिश और समुद्री तूफान ने राज्य में भारी तबाही मचाई। इस चक्रवात ने महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों को भी प्रभावित किया। दिसंबर 2023 में, चक्रवात मिकाउंग के चलते चेन्नई में भारी बारिश और बाढ़ के कारण बड़े नुकसान हुए। इसके अलावा, जुलाई 2023 में उत्तरी भारत और सिक्किम में आई बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को बुरी तरह प्रभावित किया। स्विस रे के विश्लेषण में पाया गया कि भारत में पिछले दो दशकों में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले कुल वार्षिक नुकसान का लगभग 63 फीसदी हिस्सा बाढ़ से जुड़ा हुआ है। इसका कारण भारत की जलवायु और भौगोलिक स्थिति है। भारत में गर्मी का मॉनसून (जून से सितंबर) और पूर्वोत्तर मॉनसून (अक्टूबर से दिसंबर) भारी बारिश लाते हैं, जिससे गंभीर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। कुछ बड़ी घटनाओं में 2005 में मुंबई, 2013 में उत्तराखंड, 2014 में जम्मू और कश्मीर, 2015 में चेन्नई और 2018 में केरल की बाढ़ शामिल हैं। साल 2023 में उत्तर भारत की बाढ़ ने भी एक अरब डॉलर से अधिक का नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट कहती है कि नुकसान में वृद्धि के कई कारण हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन प्रमुख है। बढ़ते तापमान से चक्रवात, बाढ़ और सूखे जैसी घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ी है। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ता निर्माण और आबादी आपदा के समय अधिक नुकसान का कारण बनते हैं। बाढ़ जैसी आपदाओं से सड़कों, पुलों और सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान होता है। इससे ना केवल आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं बल्कि यह लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित करता है। कुदरती आपदाओं के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घरों का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। इससे हजारों लोग बेघर हो जाते हैं और फिर से निर्माण में भारी खर्च आता है। प्राकृतिक आपदाओं से भारत के कुछ क्षेत्र अधिक प्रभावित हैं। तटीय राज्य, जैसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल अक्सर चक्रवात और समुद्री तूफानों का सामना करते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे गंगा के मैदान हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। राजस्थान और गुजरात बार-बार सूखे का सामना करते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी क्षेत्र भूकंप और भूस्खलन के लिए संवेदनशील है। साथ ही, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली जैसे बड़े शहर बाढ़ और जलभराव के लिए अधिक संवेदनशील हैं। वर्ष 2005 की मुंबई बाढ़ और 2015 की चेन्नई बाढ़ भारत की सबसे महंगी प्राकृतिक आपदाओं में से हैं। इनसे क्रमश- 5.3 अरब डॉलर और 6.6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। रिपोर्ट कहती है कि इन घटनाओं से स्पष्ट है कि बेहतर योजना और आपदा प्रबंधन की सख्त जरूरत है। जलवायु परिवर्तन के चलते भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता और बढने की संभावना है। स्विस रे के मुताबिक भारत को आपदा प्रबंधन और तैयारी के लिए बेहतर कदम उठाने होंगे और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा जो आपदाओं का सामना कर सके। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए स्विस रे की रिपोर्ट में कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं। जैसे कि डेटा और प्रभावित केंद्रों की पहचान कर संवेदनशील क्षेत्रों का विस्तृत नक्शा बनाना होगा। आधुनिक तकनीकों और डेटा का इस्तेमाल कर नुकसान का सटीक आकलन किया जाए। ऐसी बीमा योजनाएं तैयार की जाएं, जो अधिक लोगों तक पहुंच सकें और प्राकृतिक आपदाओं के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकें। फरवरी 2021 में उत्तराखंड में एक हिमनद के फटने के कारण बर्फ, हिम और मलबे का स्खलन होने से व्यापक फ्लैश फ्लड उत्पन्न हुआ। भारत में बाढ़ प्रतिवर्ष लगभग 75 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र को प्रभावित करती है और फसलों, घरों एवं सार्वजनिक उपयोगिताओं की क्षति के रूप में 1,805 करोड़ रुपए मूल्य की हानि का कारण बनती है। सवाल यह है कि आखिर देश के लोग बाढजनित आपदाओं की मार कब तक झेलते रहेंगे। हर साल होने वाली मौतें और हजारों करोड़ की सम्पत्ति की बर्बादी आखिर कब थमेगी। सिर्फ प्रकृति को दोष से देने से जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।

शांति, प्राकृतिक सौंदर्य और औपनिवेशिक विरासत का अनोखा मेल है कसौली

प्रीटी

हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में स्थित कसौली एक छोटा लेकिन बेहद आकर्षक और शांत पहाड़ी स्थल है। समुद्र तल से लगभग 1,900 मीटर की ऊँचाई पर बसा कसौली अपनी हरियाली, शांत वातावरण, औपनिवेशिक इमारतों और मनोरम दृश्यों के लिए जाना जाता है। यह एक आदर्श स्थान है उन लोगों के लिए जो भीड़भाड़ और शोरगुल से दूर कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं। कसौली की स्थापना 1842 में ब्रिटिश राज के दौरान एक सैन्य छावनी के रूप में हुई थी। यहाँ आज भी कई ब्रिटिश-युग की इमारतें और चर्च मौजूद हैं, जो इसके इतिहास को जीवंत बनाए रखते हैं। साथ ही, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और साफ-सुथरी जलवायु इसे एक बेहतरीन हिल स्टेशन बनाती है।

प्रमुख आकर्षण

1. **मंकी पॉइंट:** कसौली का सबसे ऊँचा स्थान मंकी पॉइंट है, जहाँ से सतलुज नदी, चंडीगढ़ और शिमला के दृश्य साफ दिखाई देते हैं। यहाँ एक छोटा हनुमान मंदिर भी है, जो धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य दोनों के लिए प्रसिद्ध है।
2. **गिल्बर्ट ट्रेल:** प्राकृतिक प्रेमियों और वॉकिंग के शौकीनों के लिए यह एक आदर्श जगह है। यह पगडंडी देवदार और ओक के पेड़ों के बीच से गुजरती है और यहां की शांति आत्मा को सुकून देती है।
3. **क्राइस्ट चर्च:** 1853 में बना यह चर्च कसौली की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। इसकी गोथिक शैली की वास्तुकला और रंगीन कांच की खिड़कियाँ देखने लायक हैं।
4. **सनसेट पॉइंट:** शाम के समय यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। पहाड़ियों के बीच सूरज को डूबते हुए देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है।
5. कसौली ब्रुअरी: यह एशिया की सबसे पुरानी डिस्टिलरी मानी जाती है, जो अब भी संचालित हो रही है। यह ब्रिटिश काल की विरासत को संजोए हुए है।

कसौली में करने योग्य गतिविधियाँ

- प्राकृतिक ट्रेल्स पर वॉकिंग और ट्रेकिंग
- स्थानीय बाजारों में शॉपिंग (हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्र, जैम आदि)
- फोटोग्राफी और बर्ड वॉचिंग
- चर्चों और औपनिवेशिक इमारतों की खोज
- शांत वातावरण में ध्यान और योग

स्वामी, भाग्यमीडिया पब्लिकेशन प्रा. लि. के लिए प्रकाशक, मुद्रक राजेश शर्मा द्वारा प्रदेश वॉच मीडिया ग्रुप 11 प्रेस काम्पलेक्स जोन-1 एम.पी. नगर भोपाल (म.प्र.) से मुद्रित कर, जी-11 प्रथम तल गोयल निकेत जोन-1 एम.पी. नगर भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित, पिन-462011, संपादक : विनोद शर्मा, फोन नं. 0755-4512708, पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार सभी मामलों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा । RNI No. MPHIN/2016/68059